

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

Hkx II—[k.M 4

PART II—Section 4

izkf/dkj ls izdkf'kr

la- 22] ubZ fnYyh] 'kqÖokj] fnlEcj 1] 2017@vxzgk;.k 10] 1939

No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939

2006 (2006 का 41) क) धारा 125 +ारा द शि-य का योग करते 1ए, भारत के राजप4, भाग-II, खंड-4 म भारत सरकार, र5ा मं4ालयक) अधिसूचना का.िन.आ. 5(अ), तारीख 22 माच:, 2017 +ारा छावनी अधिनयम, 2006 क) धारा 125 के अधीन यथाअपेित कािशत कया गया था, िजसम उ- अधिसूचना के काशन क) तारीख से साठ दन क) अविध क) समाि@ तक उन सभी ाि-य सेिजनके उससे भािवत होने क) संभावना है, आ5ेप और सुझाव आमंित कए गए थे। गया है। छावनी संपि िनयम, 1925 को अधिHात करते 1ए, उन बात के िसवाय, िजह इस अधिHमण से पूव; कया गया है या करने का लोप कया गया है, छावनी संपि संबंधी िनKिलिखत िनयम बनाती है अथा;त :- 1. 2. 7009 GI/2017 और उ- ाप िनयम के संबंध म जनता से ा@ आ5ेप और सुझाव पर क िय सरकार +ारा िवचार कया अत: अब क िय सरकार, छावनी अधिनयम, 2006 क) धारा 125 +ारा द शि-य का योग करते 1ए और (2) (3) (क) (ख) (ग) ये िनयम भारत क) सभी छाविनय को िवMतानरत हगे। ये राजप4 म उनके काशन क) तारीख को वृ हगे।

“जंगम संपि” म भूमि पर खड़ा काX, उगती फसल व घास, पेड़-पौध पर लगे फल तथा उनका रस, िवतार और आरंभ—(1) इन िनयम का संि5@ नाम छावनी संपि िनयम, 2017 है।
नई दली, 1 दस

बर, 2017 रा मंालयअधिसूचना

3. 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

छावनी संपि का रिजटर-Mथावर स

पि, जो छावनी बोड; म िनिहत है या उसक) है, के रिजMटर छावनी लेखा कोड, 1924 के िविन]द;^ प म छावनी बोड; +ारा बनाए रखा जाएगा और छावनी बोड; क) सभी धृतिय म पनरवध;न या पनरवत;न को उसम अभिलिखत कया जाएगा। के िय सरकार म" िनिहत भूमि से िभ% भूमि का&य या प'ाउपबंध के अधीन रहते 1ए, छावनी बोड;, के िय सरकार म िनिहत संपि से िभR कसी ऐसी Mथावर संपि का Hय कर सकेगा या पाे पर ले सकेगा जो छावनी के शासन से संबिधत ताQकालिक और िनिहत योजन के िलए अपेित हो :

अMवीकृत करने से पहले धान िनदेशक, र5ा स

पदा क) Nटपणी अभि@ करेगा, के िसवाय, छावनी क) सीमाे के भीतर कसी ऐसी संपि म कोई िहत अज;त नहY करेगा। भूमि अज)न का आवेदन - छावनी बोड;, अधिनयम क) धारा 124 के अधीन भूमि के अज;न के िलए के िय सरकार को आवेदन करते समय अज;न कए जाने क) आवृयकता को Mप^ प से बताएगा तथा संदाय कए जाने वाले और ेिषित कए जाने वाले ितकरका ािलन Mतुत करेगा तथा छावनी बोड; यह भी माणित करेगा क ाइवेट संिवदा +ारा अज;न असा;य या िविशेष कारण से अवांछनीय पाया गया है। सरकार म िनिहत है, छावनी शासन से संबिधत योजन के िलए छावनी बोड; +ारा अपे5ा क) जाती है तब छावनी बोड;, उन कारण को बताते 1ए क वह kय अपेित है और वह योजन दशा;ते 1ए िजसके िलए वह अपेित है, भूमि क) मंजूरी के िलए आवेदन कर सकेगा और यद क िय सरकार िवचार करती है क आवेदन मंजूर कया जाना चािहएतब ऐसी शता के अधीन जो वह ठीक समझे, भूमि को छावनी बोड; को अंतनरत कर सकेगी: (क) (ख) (ग)

छावनी बोड; 7ारा थावर संपि का अंतरण—ऐसी Mथावर संपि को, जो छावनी बोड; म िनिहत है और उसक) है, छावनी बोड;, कसी ाि- को िबना ििमयम के पाे से िभR िविहय, बंधक या िविनमय +ारा या अयथा के िय सरकार क) पूव; मंजूरी के िसवाय और ऐसे िनबंधन और शता पर जो के िय सरकार अनुमोदत करे, अंतनरत नहY करेगा: और र5ा सेवाे के िवचार अभिनिहत कए जाएंगे और संबिधत कमान

के धान िनदेशक, २५० स

पदा के माध्यम से क िय सरकार को सूचित कए जाएंगे और के िय सरकार +००० इन पर विचार कया जाएगा। छावनी बोड) ७००० प०—अधिनयम क) धारा २६७ के उपबंध के अधीन रहते १ए, वह Mथावर संपि जो छावनी बोड; म िनिहत है और उसक) है, छावनी बोड; +००० िनKिलिखत शता पर ििमयम के िबना पा० पर दी जा सकेगी अथात :— (i)

परंतु छावनी बोड;, कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी क) मंजूरी, जोक ऐसी मंजूरी को Mवीकृत या परंतु— यद ऐसी भूमि िजसके िलए आवेदन कया गया है, कसी अय योजन के िलए पहले से ही अधिभोग म है, तब ऐसी भूमि का छावनी बोड; को अंतरण, छावनी भूमि शासन िनयम, १९३७ के िनयम ७ या वृ छावनी भूमि शासन िनयम के सुसंगत िनयम के उपबंध के +००० शासित होगा; या यद भूमि ऐसे उम००० के िलए अपे०त है, िजससे छावनी बोड; को कसी कार क) आय A०QPR होगी, तब ऐसी भूमि ऐसी री०त म क) गई अदायगी पर जो के िय सरकार, Qयेक मामले म समुचित समझे, अंतर्गत क) जा सकेगी; यद कसी भी समय भूमि का उपयोग ऐसे उम००० के िलए नहY कया जाता है िजसके िलए वह छावनी बोड; को मंजूर क) गई है, या के िय सरकार क) राय म कहY अय शता के भंग होने पर, िजन पर भूमि छावनी बोड; को अंतर्गत क) गई थी, या ऐसी भूमि साधारण लोकिहत म अपे०त है, तो क िय सरकार ऐसी भूमि पर फर क०जा कर सकेगी और के िय सरकार +००० इस कार से क०जा क) गई कसी भूमि के संबंध म छावनी बोड; को संदेय ितकर क) रकम का िविनय Qयेक मामले म के िय सरकार +००० कया जाएगा और ऐसी रकम, कहY भी प०रिMथितय म उस भूमि के अंतरण के िलए छावनी बोड; +००० के िय सरकार को संद, रकम, यद कोई हो, के साथ उस पर िनम;त भवन, यद कोई हो, क) ०रि भक लागत या वत;मान मूय से, इनम से जो भी कम हो, अधिक नहY होगी।

परंतु यद Mथावर संपि छावनी क) सीमा० से बाहर अविMथत है, तो छावनी बोड; +००० रा०य सरकार पा० क)स

पूण; अविध के दौरान एक यु०-यु- भाटक आरि०त हो और संदेय हो या िवकप के प म धान िनदेशक +००० स

यक अनुमोदत उपयु- राजMव उQपादन आदश; किपत हो;

पुनवा)सन और पुनःवथापन म" .ितकर और पारद०श)ता अधिकार अधिनयम, २०१३ के अधीन

िहत भूमि का छावनी बोड) को अंतरण—जब छावनी म कसी ऐसी भूमि क), जो के िय

'Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

9.

10.

11.

(ii)

(iii) (iv)

(v) (vi)

के िय सरकार को थावर संपि अंतरण करने क० शि० - इन िनयम के अंतःव;^ कसी बात के होते १ए भी, छावनी बोड; कसी Mथावर संपिको जो इस अधिनयम क) धारा १२२ के अधीन उसम िनिहत है और उसक) है, के िय सरकार को अंतर्गत कर सकेगा कतु इस कार नहY क कसी यास या लोक अधिकार पर भाव पड़े िजसके अधीन वह संपि धा०रत है। थावर संपि अ०ज)त व अंतरत करने क० शि० - इस अधिनयम क) धारा १२३ के उपबंध के अधीन रहते १ए, छावनी बोड;, कसी ऐसी जंगम संपि को अ०ज;त कर सकेगा जो इस अधिनयम के योजन के िलए अपे०त हो और कसी ऐसी जंगम संपि को जो छावनी बोड; म िनिहत है या उसक) है, कसी री०त म या कही ऐसे िनबंधन पर अंतर्गत कर सकेगा जो साधारण अधिवेशन म पा०रत संकप +००० समीचीन और यु०-संगत अवधा०रत कर। रा सःपदा अधिकारी ७००० .वेश, िनरीण(१)

(2)

पा० या पा० के िलए कया गया करार, छावनी बोड; के साधारण अधिवेशन म कए गए संकप +००० उसक) पूव; मंजूरी के िबना कसी भी अविध के िलए या कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी क) पूव; मंजूरी के िबना ऐसी अविध के िलए जो बीस वष; से अधिक है और तीस वष; से अधिक नहY है या के िय सरकार क) पूव; मंजूरी के िबना ऐसी अविध के िलए जो तीस वष; से अधिक है, नहY कया जा सकता; ऐसे योजन के िलए पा० िजसके िलए, छावनी बोड; अधिनयम क) धारा १२३ के अधीन Mवयं उपयोजन नहY कर सकता था, संपि के िलए के िय सरकार क) पूव; मंजूरी अपे०त होगी; Qयेक पा० पर, वे शत०Mप^ प से िविनजद;^

क) जाएंगी, जिस योजना या योजना के लिए पाए पर दी गई संपि का पाएदार +ारा उपयोग किया जा सकेगा और उसमें छावनी बोर्ड; को इस बात के लिए शि- दान करने वाला खंड होगा क छावनी बोर्ड; क) स मित के बिना कसी अय योजना के लिए संपि का उपयोग कए जाने क) दशा म वह पाए को निराकृत कर दे; छावनी बोर्ड;, के िय सरकार क) पूव; मंजूरी के बिना, खंड (iv) के अनुसरण म इसक) स मित नहय देगी यद ऐसी स मित, पाए पर दी गई संपि के ऐसे योजना के लिए उपयोग के लिए चाही गई है जिसके लिए Mवयं छावनी बोर्ड; भी इस अधिनयम क) धारा 123 के अधीन संपि का उपयोग नहय करता; जहां पाएदार, पाए क) निबंधन के उलंघन म और छावनी बोर्ड; क) स मित के बिना पाए पर दी गई संपि का कसी योजना के लिए ऐसा उपयोग करता है जिसके लिए Mवयं छावनी बोर्ड; भी अधिनयम क) धारा 123 के अधीन उस संपि का उपयोग नहय कर सकता तो छावनी बोर्ड; ऐसे पाए को तुरंत निराकृत कर देगा, ऐसी संपि का नया पाआ केवल के िय सरकार क) पूव; मंजूरी तथा के िय सरकार +ारा निदेशित ऐसी शता पर दान किया जाएगा: परंतु अधिनयम क) धारा 257 के उपबंध के अधीन, ऐसी Mथावर संपि जो पथ है या जिसमें कसी पथ का भाग सि मिलत है, पाए पर नहय दी जाएगी।

रडा स

पदाधिकारी या साधारण या विशेष आदेश +ारा उसके +ारा अधिकृत कोई Aि-, सहायक या कम;कार के साथ या उनके बिना, अधिनयम क) धारा 122 के अधीन छावनी बोर्ड; म निहित कसी भवन म या भूमि पर कोई ऐसी जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सवर्ण करने के योजना के लिए वेश कर सकेगा, जो ऐसे अधिकारी या Aि- आवृयक समझे या कसी ऐसे संकम; के परीक्षण या निरीक्षण के लिए आवृयक समझे जो ऐसे भवन या भूमि पर निःपादत 1 आ है या होता रहा है या जिसे निःपादत किया जाना है। उप-नियम (1) म विनिर्द;^ कत;A के पालन म, ऐसा अधिकारी या Aि- उहय Hयाe का पालन करेगा जो अधिनयम के अुयाय XV म वेश और निरीक्षण योजना के लिए अभिकथित हW।[फा. सं. 14(4)/2009-डी (क्यू एवं सी)]मनीष ठाकुर, संयु- सिचव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

S.R.O. 31(E).—Whereas a draft of certain rules relating to the Cantonment property which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 125 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), was published as required under section 125 of the Cantonments Act, 2006 in notification of the Government of India in the Ministry of Defence vide S.R.O. 5(E), dated the 22nd March, 2017 in Gazette on India, Part – II, Section 4, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty day from the date of publication of the said notification.

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 125 of the Cantonment Act, 2006 and in supersession of the Cantonment Property Rules, 1925 except as regard things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules relating to the Cantonment property, namely:—

1. Short title extend and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonment Property Rules, 2017.

(2) These rules shall extend to all cantonments in India.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise require,

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) "immovable property" includes land, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to things attached to the earth but does not include standing timber, growing crops or grass;

(c) "movable property" includes standing timber, growing cops and grass, fruit upon and juices in trees, bark, lac and property of every other description except immovable property.

3. **Register of cantonment property.**—Registers of immovable property, which vest in and belong to the Cantonment Board, shall be maintained by the Cantonment Board in the forms specified in the Cantonment Account Code, 1924 and all additions to or alterations in the holdings of the Cantonment Board shall be recorded therein.
4. **Purchase or lease of land other than land vested in the Central Government.**—Subject to the provisions of section 123 and section 124 of the Act, the Cantonment Board may purchase or take on lease any immovable property, other than property which is vested in the Central Government that may be required for immediate and definite purpose connected with the administration of the cantonment:

Provided that the Cantonment Board shall not acquire any interest in any such property within the limits of the cantonment except with the sanction of the General Officer Commanding-in-Chief, the Command, who shall obtain comments of the Principal Director, Defence Estates before according or refusing sanction.

5. **Application for acquisition of land under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.**—In making an application to the Central Government under section 124 of the Act for the acquisition of land, the Cantonment Board shall state clearly the necessity for the acquisition and shall submit an estimate of the compensation to be paid and any revenue to be remitted and the Cantonment Board shall also certify that acquisition by private contract has been found impracticable or is, for special reasons, undesirable.
6. **Transfer of land vested in the Central Government to Cantonment Board.**—When any land in the cantonment, which is vested in the Central Government, is required by the Cantonment Board for a purpose connected with the administration of the cantonment, the Cantonment Board may

१Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

apply to the Central Government for the grant of the land stating the reasons and purpose for which it shall be utilised and if the Central Government considers that the application shall be accepted, they may transfer the land to the Cantonment Board on such conditions, if any, as they may think fit:

Provided that –

- (a) if the land applied for is already occupied for any other purpose, its transfer to the Cantonment Board shall be governed by the provisions of rule 7 of the Cantonment Land Administration Rules, 1937 or by the relevant rule of the Cantonment Land Administration Rules in force; or
 - (b) if the land is required for an object from which the Cantonment Board will derive income of any description, it may be transferred to the Cantonment Board only on such payment made in such manner as the Central Government may consider equitable in each case;
 - (c) if at any time the land is not used for the object for which it was granted to the Cantonment Board, or if there has been, in the opinion of the Central Government, any other breach of the conditions on which it was transferred to the Cantonment Board, or if the land is required for a general public purpose, the Central Government may, after giving opportunity to the Cantonment Board to show cause and considering the cause shown, resume possession of the land and for any land so resumed by the Central Government the amount of compensation payable to the Cantonment Board shall be decided by the Central Government in each case and shall in no circumstances exceed the amount, if any, paid to the Central Government by the Cantonment Board for the transfer of the land together with the initial cost or the present value, whichever is less, of buildings, if any, erected thereupon.
7. **Transfer by Cantonment Board of Immovable Property.**—Immovable property which vests in and belongs to the Cantonment Board shall not be transferred to any person by the Cantonment Board by way of sale, mortgage or exchange, or otherwise than by lease without a premium, except with the previous sanction of the Central Government and in such manner and on such terms and conditions as the Central Government may, approve such sanction:

Provided that if the immovable property is situated beyond the limits of the Cantonment, the views of the State Government and the services shall be ascertained by the Cantonment Board and communicated to the Central Government through the Principal Director, Defence Estates, the Command, shall be taken into consideration by the Central Government.

8. **Lease by Cantonment Board.**—Subject to the provisions of section 267 of the Act, immovable property which vests in and belongs to the Cantonment Board may be leased by the Cantonment Board without a premium on the following conditions, namely:-
- (i) that a reasonable rent is reserved and made payable during the whole term of the lease or, in the alternative, a suitable revenue generating model duly approved by the Principal Director is devised;
- (ii) that the lease, or the agreement for the lease, is not made for any term without the previous sanction of the Cantonment Board by resolution at a general meeting; or for any term exceeding five and not exceeding twenty years without the sanction of the Principal Director; or for any term exceeding twenty and not exceeding thirty years without the sanction of the General Officer Command-in-Chief, the Command; or for any term exceeding thirty years without the sanction of the Central Government.
- (iii) that a lease for any purpose for which the Cantonment Board itself could not, utilize the property, under section 123 of the Act, shall require the previous sanction of the Central Government;
- (iv) that every lease shall specify in clear terms the purpose or purposes to which leased property may be put by the lessee, and shall contain a clause empowering the Cantonment Board to abrogate the lease in the event of the property being used for any other purpose without the consent of the Cantonment Board;
- (v) that the Cantonment Board shall not give its consent in pursuance of clause (iv) without the previous sanction of the Central Government if such consent is sought for use of the leased property for a purpose for which the Cantonment Board could not itself apply the property under section 123 of the Act;
- (vi) that where the lessee, in contravention of the terms of the lease and without the consent of the Cantonment Board, uses the leased property for any purpose to which the Cantonment Board could not itself utilize the property under section 123 of the Act, the Cantonment Board shall forthwith abrogate the lease, and any fresh lease of the same property to the lessee shall be granted only with the previous sanction of the Central Government and on such terms as the Central Government may direct:
- Provided that subject to the provisions of section 257 of the Act, any immovable property which is, or includes a part of a street shall not be given on lease.
9. **Power to transfer immovable property to the Central Government.**—Notwithstanding anything contained in these rules, the Cantonment Board may transfer to the Central Government any immovable property which vests in and belongs to it under section 122 of the Act, but not so as to affect any trusts or public rights subject to which the property is held.
10. **Power to acquire and transfer movable property.**—Subject to the provisions of section 123 of the Act, the Cantonment Board may acquire any movable property that may be required for the purposes of the Act, and may transfer any movable property which vests in and belongs to the Cantonment Board in any way and on any terms that it may, by resolution at a general meeting, determine to be expedient and reasonable.
11. **Entry, inspection by Defense Estates Officer.**—
- (1) The Defence Estates Officer, or any person authorised by him by general or special order may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any building or land vesting in Cantonment Board under section 122 of the Act, for the purpose of making any enquiry, inspection, measurement, valuation or survey, which such officer or person may consider necessary, or of examining or inspecting any works which have been, are being, or are to be executed in or on such building or land.
- (2) In the performance of the duties specified in sub-section (1), such officer or person shall observe the same procedure for the purposes of entry and inspection as is laid down in Chapter XV of the Act.

[F. No. 14(4)/2009-D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

	चतुसदमयस		
--	----------	--	--

	क-अबाला छावनी		
	बोर्ड का नाम (2)	वार्ड नं. जिसमें रिई	
		है- (3) VII	

शिय-कायोंम करते 1ए, क ीय सरकार अधिसूचित करती है क िनकिलिखत सारणी म िविनाद;^ छावनी बोर्ड क)

2. 3. फतेहगढ़ फतेहगढ़ (अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) क) धारा 12 क) उपधारा (8) +ारा द

III II

नई दली, 1 दस

बर, 2017

ी शिश मोहन, िनवा

चित सदय का छावनी अधिनियम, 2006 क धारा 34 क उपधारा (4) के साथ प-
ठत धारा 34 क उपधारा (2) के अधीन भारत सरकार, र0ा मं2ालय के आदेश
सं. 256/एफ़/2016-डी(:यू एवं सी) तारीख 31.10.2016 =ारा हटाया जाना।ी रतन
कुमार, िनवा

चित सदय का छावनी अधिनियम, 2006 क धारा 34 क उपधारा (4) के साथ प-
ठत धारा 34 क उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन भारत अधिसूचना

1Hkkx IIµ[k.M 4°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7

4. Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby notifies that the following vacancies have occurred in the elected membership in respect of the Cantonment Boards specified in the table below, namely:— ज़ामू
S.R.O. 32(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (8) of section 12 of the Cantonments VI

New Delhi, the 1st December, 2017 सरकार, र0ा मं2ालय के आदेश सं. 76/ 38 /िनवा

चित सदय/हताना/21/2/सी /

TABLE [फा. सं. 14(2)/2012-डी(kयू एंड सी)/वॉल-II]
मनीष ठाकुर, संयु. सिचव

Sl. No.	Name of Cantonment	Ward No. in which vacancy has occurred	Reason for occurrence of vacancy
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ambala	VII	Death of Late Shri Garib Dass, Elected Member on 22.02.2017.
1.	Fatehgarh	II	Removal of Shri Shashi Mohan, Elected Member under sub-section (2) of Section 34 read with sub-section (4) of section 34 of the Cantonments Act, 2006, vide Government of India, Ministry of Defence order No. 256/E/2016-D(Q&C) dated 31.10.2016
2.	Fatehgarh	III	Removal of Shri Ratan Kumar, Elected Member under clause (b) of sub-section (1) of Section 34 read with sub-section (4) of section 34 of the Cantonments Act, 2006, vide Government of India, Ministry of Defence order No. 76/38/Elected Member/Removal/21/2/C/DE/ 15/281/E/16/D(Q&C) dated 28.12.2016
3.	Jammu	VI	Death of Late Shri Harmohinder Singh, Elected Member on 16.09.2016.

[F. No. 14(2)/2012-D(Q&C)/Vol-II]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

शिशु का योग करते हैं, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में विनियमन छावनी बोर्डों के संबंध में आकिममकरिय को भरने के लिए कराए जाने वाले आकिममक निवाचन के लिए 22 जनवरी, 2018 को निवाचन के तारीख के पश्चात् सं. (1) 1. 2. 3.

(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के धारा

15 के उपधारा (2) द्वारा दर्ज दली, 1 दस
बर, 2017

छावनी बोर्ड का

नामफतेहगढ़

अंबाला

अधिसूचना

ज

मू(2)

[फा. सं. 14(2)/2012-डी(क्यू एंड सी)/वॉल-II] मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव II एवं III वाड सं. (3) VII

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

S.R.O. 33(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby directs the 22nd January, 2018 as the date on which casual elections to fill the casual vacancies in respect of the Cantonment Boards specified in the table below shall be held, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of Cantonment Boards	Ward No.
(1)	(2)	(3)
1.	Ambala	VII
2.	Fatehgarh	II and III
3.	Jammu	VI

[F. No. 14(2)/2012-D(Q&C)/Vol-II]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

Digitally signed by RAKESH

RAKESH SUKUL SUKUL Date:

2017.12.01 21:16:04
+05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.